(1900/VVK/VPN)

सेंटर और स्टेट के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियाँ भी स्पष्ट कर दीं।

मान्यवर, ऑल एजेंसी अप्रोच शुरु की। सिर्फ हथियार नहीं, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम सभी पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए। मैं बाद में आँकड़ा बताता हूँ। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा और पहले जहाँ राज्य की उपस्थिति नहीं थी, स्टेट नहीं था, वहाँ आज राज्य की उपस्थिति है और नक्सलवाद की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य अब हर गाँव में पहुँच चुका है, वहाँ पंचायत बन चुकी है।

मान्यवर, विकास के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ली और सुरक्षा नकेल कसने के लिए होल ऑफ एजेंसी अप्रोच ली। मान्यवर, तीन चीजें, आज मैं देश के सामने तीन तिथियाँ जरूर बताना चाहता हूँ। 24 अगस्त 2024, 20 अगस्त 2019 और कल 31 मार्च 2026। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई। मोदी जी ने विकास का काम तो पहले ही चालू कर दिया था। पुलिस को-ऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके को-ऑर्डनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ ये सब 20 अगस्त को डिजाइन किया गया, तो फिर इतनी देर क्यों लगी? … (व्यवधान) बैठ जाओ, मैं पैसे के बारे में भी बताता हूँ।

मान्यवर, देर क्यों लगी, क्योंकि बीच में, छत्तीसगढ़ में काँग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूँ। बिहार वर्ष 2024 से पहले नक्सलमुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र, एक तहसील छोड़कर वर्ष 2024 से पहले नक्सलमुक्त हो चुका था। ओडिशा वर्ष 2024 से पहले नक्सलमुक्त हो चुका था। झारखंड, एक जिला छोड़कर वर्ष 2024 से पहले नक्सलमुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ काँग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर, किसी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ काँग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा था।

मान्यवर, दूसरी तारीख आती है, 24 अगस्त 2024। वर्ष 2024 की शुरुआत में … (व्यवधान) हाँ, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कह रहा हूँ। मुझे रूल्स न समझाएँ। व्यक्ति के सामने यदि करना है, तो भूपेश बघेल को पूछो, प्रूफ रजू करूँ क्या यहाँ पर? हाँ बोले, तो बोलो, वर्ना फँस जाओगे। … (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, उसके दूसरे ही महीने मैं वहाँ गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया। साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त को मैंने घोषित किया था कि 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो हुआ, वह मैं बताना चाहता हूँ।

(1905/SK/UB)

महोदय, हमने सुरक्षा घेरे में बढ़ोतरी की। माननीय मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए। वर्ष 2014 में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे और अब सिर्फ दो बचे हैं। वर्ष 2014 में 35 मोस्ट अफेक्टेड जिले थे और अब शून्य हैं। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले 350 पुलिस स्टेशन थे अब सात हैं। पिछले छ: सालों में 406 नए सीएपीएफ कैम्प बनाए गए, 68 नाइट लैंडिंग हैलीपेड बनाए गए, 400 बुलेट और ब्लॉस्ट प्रूप गाड़ियां जवानों को दी गईं, पांच अस्पताल जवानों के लिए बनाए गए और कॉम्युनिकेशन की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की गई।

मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए इसलिए मैं ये आंकड़े उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं वर्ष 2024, 2025 और 2026 का संयुक्त आंकड़ा पढ़ रहा हूं। मार्च, 2026 यानी तीन साल में 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और 2218 गिरफ्तार हुए। हमने उनको पकड़कर जेलों में डाला और अदालतों की शरण में ले गए। 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया और ये हमसे संवाद करने की बात कर रहे हैं। 2218 जेल में गए और सिर्फ 706 लोग, जिन्होंने सरैंडर नहीं किया, इनको बैन में रखा गया था, और इनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मैं कहता हूं कि शासन की यही एप्रोच होनी चाहिए कि जो वार्ता करना चाहता है, उसके साथ वार्ता करनी चाहिए और जो किसानों, बच्चों, आदिवासियों और जवानों पर गोली चलाता है, उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल है और यही शासन का नियम है।

मान्यवर, हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों का उपयोग किया है। हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सटीक निगरानी और ढेर सारे टेलीफोन बिलों का विश्लेषण किया। गृह मंत्रालय ने लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, फोरेंसिक और तकनीकी संस्थानों की सहायता लेकर पूरे अभियान का नेतृत्व किया। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट का उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और एआई आधारित डेटा एनालिसिस से सफलता प्राप्त हुई।

महोदय, कई ऐसे अभियान चले जिसने बड़े-बड़े क्षेत्र क्लियर कर दिए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हमारे जवानों के साथ अन्याय होगा। वर्ष 2022 में 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' बिहार में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में चला। वर्ष 2022 में 'ऑपरेशन डबल बुल गुमला', लोहरदगा और लातेहार में चला और 8 से 25 फरवरी में तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। 1- 3 सितम्बर, 2022 में 'ऑपरेशन थंडर स्ट्रॉम' झारखंड के सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में चला। वर्ष 2022 में जून-जुलाई महीने में 'ऑपरेशन भीमबांध' मुंगेर जिले में चला। वर्ष 2022 में 'ऑपरेशन चक्रबांधा' बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में चला। ये सारे एरियाज़ इससे मुक्त हो गए।

मैं सदन का ध्यान एक और 'ऑपरेशन ब्लैक फोरेस्ट' की तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैम्प बनाया था। ये लोग पांच साल लड़

सकें, इनके पास इतना असलहा और हथियार थे। वहां सोलर लाइट की व्यवस्था है, ढेर आईडी बनाने की फैक्ट्रियां थीं। वहां पांच साल का अनाज भरा था और 400-500 कैडर एकत्रित थे। मैं आज बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी।

(1910/AB/NKL)

पहाड़ पर 45 डिग्री टेम्परेचर था, 10 बजते-बजते पत्थर गरम हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर, 3 लीटर पसीना बह जाता था, हम जवान को पीने के लिए राशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ़ नहीं की मान्यवर, 21 दिन तक ऑपरेशन चला, 30 से ज़्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए और यह पूरा असलहा हमने ज़ब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत किया।

मैं आज भी बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े भाव के साथ … (व्यवधान), सुनिए न, आगे सुनिए। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मनपूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूँ मान्यवर। इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग करके इनके किले को तोड़ा है। ओवैसी जी कह रहे हैं ग्रेहाउंड्स, ग्रेहाउंड्स का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से न बोल दिया था कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद, जो नीचे आए इनको रोका है, ऊपर नहीं आए।

मान्यवर, यह आज जो वर्ष 2024 की इनकी मुख्य कैडर है , मैं आज इसकी स्थिति बताना चाहता हूँ। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर वर्ष 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, एक पकड़ा गया है, सात सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और एक फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है, मुझे लगता है वह भी बहुत जल्दी सरेंडर कर देंगे। 21 के 21 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और उनकी केंद्रीय व्यवस्था टूट चुकी है।

दंडकारण्य में 27 की स्टेट कमेटी थी। तीन अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और दो से बातचीत चालू है, वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य, जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी, वह समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) स्टेट कमेटी, तीन सरेंडर कर गए, तीन की ही बची थी। ओडिशा, चार बचे थे, एक सरेंडर करा, तीन मारे गए। ओएससी, ओडिशा, पांच सरेंडर करे, पांच मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब्ड रीजन ब्यूरो, अरेस्ट एक हुआ, तीन मारे गए, एक फरार है खाली मान्यवर, एक ही फरार है, तो छह के छह हो गए। तेलंगाना में छह सरेंडर हो गए, तीन मारे गए, एक भी नहीं बचा है। उनकी पोलित ब्यूरो मेंबर और सीएमसी यह पूरा समाप्त हो चुका है। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूँगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं है।

मान्यवर, इनके महासचिव बसवराजू न्यूट्रलाइज हुए। हिड़मा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदरी सत्यनारायण राव रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पुल्लूरी प्रसाद राव चंद्रन्ना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेर मांझी देबू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया।

(1915/VB/VR)

थिप्परी तिरुपति 44 वर्षों से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं।

मान्यवर, हमने बिल्कुल ल्यूक्रेटिव पुनर्वसन पॉलिसी को भी अपनाया है। आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये घोषित की गई है, सामूहिक सरेंडर के लिए इस राशि को दोगुना कर दिया जाता है, सबको सरकार की ओर मोबाइल दिया जाता है, हथियार जमा कराने पर और मुआवज़ा देते हैं, पुनर्वसन केन्द्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं, हम उनको 10 हजार रुपये प्रति माह 36 महीने तक देते हैं, सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का गिफ्ट दिया है, नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांवों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये दिये जाते हैं।

मान्यवर, हमने सरेंडर हेतु कैम्प लगाये हैं। मैं आज इस सदन को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूँ। मैं उन कैम्प्स में गया हूँ। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं कैम्प्स में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवी-नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम वहां जाते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे दृश्य सामने होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं, तो वह उसे लगाते-लगाते रो पड़ती है। उसके ट्यूटर पूछती है कि क्यों रो रही हो, तो वह कहती है कि मैंने जीवन में पहली बार नेल पॉलिश लगाया है। मैं सात साल की थी जब ये मुझे उठा ले गये थे, तब से मैं पैंट, शर्ट और बूट में ही घूम रही हूँ। मैंने ऐसे जीवन को कभी देखा ही नहीं। वे लिपस्टिक लगाते-लगाते रो पड़ती हैं, जब हाथों में मेहंदी लगती है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता।

मान्यवर, बस्तर में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहां उनके मां-बाप से मिलने के लिए ले जाते हैं, खुद तो मां-बाप का आशीर्वाद लेते हैं, नये जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं और कुछ लोग मां-बाप को यह कहते हुए पीटने लगते हैं कि नक्सलियों को क्यों दे दिया, क्यों हमारा जीवन बर्बाद कर दिया? वे पच्चीस-तीस साल तक न पढ़े, न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, न रात देखा न दिन देखा, उनका पूरा जीवन ही तबाह हो गया। जिसको भी नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगता है, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि वे कैम्प्स में जाकर दो रात बिताइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन नक्सलवादियों ने क्या किया है।

यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, ऐसा कहना बहुत सरल है। है किसी के पास जवाब? 15 हजार बच्चों के जीवन बर्बाद कर दिये गये, इसका कौन जिम्मेदार है? है किसी के पास जवाब? सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल कैम्प्स में जाकर देखें कि आपने क्या किया है। आप तो ए.सी. चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन में आर्टिकल लिखते रहते हैं, लेकिन वहां जीवन के जीवन उजड़ गये हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमैन राइट का चैम्पियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमैन राइट की चिंता कौन करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेन्द्र मोदी करेंगे और कोई नहीं करेगा। इनका जो अधिकार छीन लिया गया है, उसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूँ, कर्मों में मानता हूँ। जिन्होंने भी नक्सलवादियों का शब्द से भी प्रछिन्न समर्थन किया है, वे सब इस पाप के उतने ही भागीदार हैं, जितना बंदूक लेकर घूमने वाले।

मान्यवर, हमने इनकी नौकरी और रोज़गार के लिए ढ़ेर सारे प्रयास किए हैं। हमने कौशल केन्द्र बनाये हैं। इनके बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, महिलाओं को दो लाख रुपये और पुरुषों के लिए पांच लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है।

हम बस्तर ओलम्पिक्स और बस्तर पंडुम के माध्यम से खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर अब 1,20,000 कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भागीदारी की है और 5,50,000 आदिवासी लोगों ने खेल खेला।

मेरा विपक्ष के उन सभी सदस्यों से विनती है कि जो इसे न्याय की लड़ाई कहते हैं, वे बस्तर पंडुम और बस्तर ओलम्पिक्स में जाएं।

(1920/SJN/PBT)

मान्यवर, जिनके पैर उड़ गए, हाथ कट गए, आंख चली गई, मेरे घर पर ऐसे लोग आए थे, उन्होंने नाश्ता किया था। मैं उनकी वेदना जानता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको बुलाया था। उनके लिए कभी एक घंटा तो निकालिए। उन पर जुल्म ढाहने वालों पर भाषण देने के लिए आपके पास बहुत समय है। उस जुल्म का परिणाम देखने के लिए आप एक घंटे का समय निकालिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

मान्यवर, वर्ष 1970 से नक्सली आतंकवाद क्यों फैला है, मैं अंत में उसकी तह में भी जाना चाहता हूं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, तब एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) बनी थी। हमने प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सुना था, संसद में बहस के दरमियान सदस्य सलाह दें, हमने वह भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक्सट्रा संवैधानिक फोरम खड़ी की गई थी, जो देश के लिए कानून बनाता था। उस फोरम में कौन था? सोनिया जी, इसकी अध्यक्ष थीं। हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके एनजीओ 'अमन वेदिका' में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी। यह रिकॉर्ड में है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थीं, जिन्होंने अर्बन एरियाज़ में अपहरण के केसेज़ किए थे।

मान्यवर, यह एनएसी देश के लिए नीति निर्धारण करती थी। राम दयाल मुंडा जी कहते थे कि नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर हैं। इस प्रछिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत

बढ़ाई है। शबनम हाशमी, राम पूनानिया, उषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, जीन ड्रेज, फ़राह नक़वी और एक विनायक सेन थे, वर्ष 2010 में वे अदालत द्वारा दोषी पाए गए थे, फिर भी उनको प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया था। एक महेश राउत नामक नक्सली था, जयराम रमेश जी ने उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

मान्यवर, नंदिनी सुंदर, रामचन्द्र गुहा, ईएएस शर्मा जैसे लोग सल्वा जुडूम के केस के साथ भी जुड़े हुए थे। जब देश की सर्वोच्च सत्ता के केन्द्र केन्द्र सरकार में एक एक्सट्रा संवैधानिक अथॉरिटी हो, जो प्रधानमंत्री के भी ऊपर थी, वे उसके सदस्य हों, अगर नक्सलवाद के समर्थक हों, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा। यह कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भाग नहीं सकते हैं। यह तो इतिहास है। मेरी बात पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसी सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएंगी, जो आपके कारनामों से भरी हुई होंगी। आप कैसे भागेंगे? लोकतंत्र के अंदर किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती है।

मान्यवर, वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रूरल डेवलेपमेंट फेलोशिप लॉन्च की थी। उनका काम युवाओं को एक्सपोजर देना था। उसमें महेश राउत फेलो बने थे, जो महाराष्ट्र पुलिस के नक्सलियों के साथ संबंध की वजह से महाराष्ट्र पुलिस के केस में जेल गए थे। जब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री रूरल डेवलेपेंट फेलोशिप लॉन्च हुई थी, तो उसका एक लाभार्थी नक्सलवादी है, तो नक्सलवादियों के हौसले भला कैसे टूटेंगे? ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : आपने कहा है कि उसने हथियार डाल दिए हैं। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, वर्ष 2010 में गृह मंत्री चिदंबरम जी ने चिंतलनार, छत्तीसगढ़ में एक वक्तव्य दिया था कि एक साथ 76 जवानों को मार दिया गया था। अभी अमरा राम जी जेएनयू का महिमा मंडन कर रहे थे। जेएनयू में उत्सव मनाया गया था।

(1925/DPK/SNT)

वहां एक नृत्य किया गया कि पुलिस 76 के जवान मारे गए। उस नृत्य के समय जमीन पर भारत का तिंरगा बिछाकर और उसे पैरों के नीचे रखकर नृत्य किया गया। ये इसका समर्थन करते हैं।

मान्यवर, 76 जवानों के मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता है और पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। चिदंबरम साहब ने नक्सलियों से कहा – "हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं।"

मान्यवर, किस प्रकार से यह देश चला है? पूरे तालाब में पानी भरा है, उसमें ये गोता लगाते हैं, कपड़े भिगोये बगैर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसे जादूगर देखे ही नहीं हैं कि आदमी तालाब में गोता लगा दे और बाहर निकले, तो एक भी कपड़ा

भीगा न हो और ये कहेंगे कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो गया ही नहीं और मैं तो बोला-चाला भी नहीं। इन्हें कमाल का जादू आता है। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं अब उनके नेता राहुल गांधी जी की बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठनों ने हिस्सा लिया है। इसका रिकॉर्ड है। इन्होंने वर्ष 2010 में ओडिशा में लाडो सिकाका के साथ मंच साझा किया। सिकाका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। वर्ष 2018 में इन्होंने हैदराबाद में गुम्माडी विठ्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो उस विचारधारा के करीब रहे। … (व्यवधान) इन्होंने मई, 2025 को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस के साथ मुलाकात की। … (व्यवधान)

मान्यवर, 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, तो इंडिया गेट पर नारे लगे – "कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा।" … (व्यवधान) उस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। ये कैसे बच सकते हैं? … (व्यवधान) इन्होंने वर्ष 1970 से लेकर मार्च, 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है और नरसंहार का समर्थन किया है। … (व्यवधान) जो 20,000 लोग मारे गए हैं, अगर उनका कोई एक दोषी है, तो वह कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है।… (व्यवधान) नक्सलों के साथ रहते-रहते यह पार्टी और इनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। … (व्यवधान) यह बात यहां पर रुकेगी नहीं। यह बात जनता की अदालत में जाएगी। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। … (व्यवधान)

मान्यवर, एक बार फिर से इस लड़ाई में जिस-जिस फोर्स के जो-जो जवान शहीद हुए हैं, अपाहिज हुए हैं और जो-जो नागरिक मारे गए हैं, मैं उन सबको पूरे सदन की ओर से मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर अपनी बात बात को पूरा करता हूं। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1929 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 / 11 चैत्र, 1948 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।